

एससीआर के विकास के लिए ग्लोबल टेंडर

निशांत यादव • लखनऊ

एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र) की तरह राजधानी लखनऊ तथा आसपास के जिलों को मिलाकर एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) जल्द आकार लेगा। एससीआर में मेट्रो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, उपनगरीय बसों जैसी परिवहन सुविधाओं के साथ बड़े स्तर के सुनियोजित विकास का आकलन करने के लिए जल्द ही रिक्वेस्ट फार प्रपोजल अपलोड किया जाएगा। ग्लोबल टेंडर के जरिए विदेशों में भी डेवलपमेंट प्लान बनाने वाली एजेंसियों को एससीआर की प्लानिंग का मौका मिलेगा। शनिवार को एलडीए के साथ एससीआर के प्रस्तावित विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया।

एससीआर में प्रस्तावित सभी जिलों का ड्राफ्ट वहां के विकास प्राधिकरण बनाएंगे। ग्लोबल टेंडर से चयनित एजेंसी ड्राफ्ट के आधार पर इन जिलों का एकीकृत प्लान बनाएंगी। वह 2047 तक का विजन डाक्यूमेंट बनाएंगी, जिसमें एयरपोर्ट, शहर के सुंदरीकरण सहित सभी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। एससीआर का मुख्यालय लखनऊ होगा। वहीं, एलडीए को ही एससीआर की नोडल एजेंसी बनाया गया है। लखनऊ और कानपुर



- स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए अपलोड होगा रिक्वेस्ट फार प्रपोजल
- नोडल एजेंसी एलडीए के साथ बैठक में निर्णय

8

जिलों को मिलाकर बनाया जा रहा है एससीआर

38

हजार वर्ग किलोमीटर होगा एससीआर का क्षेत्रफल

मूलभूत ढांचे के साथ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य

अगले 24 साल की जरूरतों के अनुसार होटल, बड़े संस्थान, आवासीय योजनाएं, बड़े-बड़े पार्क जैसे विकास कार्य और स्मार्ट परिवहन को लेकर प्लानिंग की जाएगी। एससीआर का उद्देश्य नया

औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना भी है। आसपास के जिलों में होटल और इंडस्ट्री के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे उनका लखनऊ की तरफ पलायन भी रुकेगा।

विकास प्राधिकरण बड़े पैमाने पर प्लानिंग करते हैं, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात जैसे जिलों में सुनियोजित विकास न हो पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर को मिलाते हुए बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात जिलों के बीच विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एनसीआर

की तरह एससीआर को बनाने के आदेश दिए थे। एससीआर का दायरा पहले 34 हजार वर्ग किमी. रखा गया था, इसे बढ़ाकर 38 हजार वर्ग किलोमीटर किया जाएगा। लखनऊ और बाराबंकी विकास प्राधिकरण में आने वाले नए जिलों को भी शामिल किया जाएगा।

दर्जनभर छोटे-बड़े शहरों में विकसित होगी नई टाउनशिप >> 9